



संस्करण : ग्वालियर

वर्ष : 03

अंक : 134

पृष्ठ : 6

मूल्य : 2.00

शनिवार,13 दिसम्बर 2025

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज ,से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 घर में घुसकर गर्लफ्रेंड को मारी गोली,कंधे और हाथ में

4 संसद के लिए काला दिन

5 राधिका आटे बोलीं- 'आजकल की शोर वाली फिल्मों से अलग है वाली

देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत

सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ

प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागकंरी में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान पाठशाला

में खेती की चुनौतियों और उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11 प्रतिशत

हिस्सा है लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21 फीसदी योगदान देता है। यह बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सीएम योगी शुक्रवार को हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव में पद्मश्री और प्रगतिशील किसान सम्मेलन वर्मा के फर्म पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम योजनाएं चलाई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ने बड़े स्तर पर किसानों को रहत दी

है। सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ-साथ यदि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियों, फल उत्पादन और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को अपनाने से सीमित भूमि पर भी शानदार उत्पादन संभव है। सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी प्रगति के बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार हर जिले में किसान प्रशिक्षण, मॉडल फर्म और आधुनिक मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन

पीएम मोदी समेत सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि



लातूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके गृह नगर लातूर में निधन हो गया। परिवार के सूत्रों ने बताया कि पाटिल कुछ समय से बीमार थे और उन्होंने अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। वह 90 वर्ष के थे। वह लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल चुके थे। पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट से सात बार जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र

से कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा, श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से दुःख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केन्द्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम किया। वह समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पिछले

कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति H प्रधानमंत्री ने श्री पाटिल से हुयी मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया। गौरतलब है कि श्री पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, पाटिल का शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्री शिवराज पाटिल जी का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि !

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बस दुर्घटना में

9 लोगों की मौत, 22 अन्य घायल

चिंतूर । आंध्र प्रदेश के अल्लुप्पूरी सीताराम राजू जिले में शुक्रवार को एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिससे कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए।

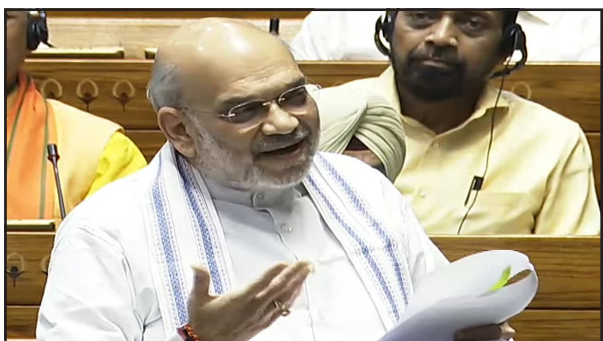


सुबह करीब 4.30 बजे हुई। बरदार ने न्यूज एजेंसी को बताया, घाट रोड सड़क से बस के नीचे गिर जाने के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। बस पूरी तरह से घाटी में नहीं गिरी। बस पलट गई... और वहीं फंस गई। उन्होंने कहा कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है। अधिकारी के अनुसार, संभवतः घने कोहरे के कारण बस चालक दुर्घटनास्थल पर स्थित मोड़ को नहीं देख पाया, जो मोथुगुड्डम थाना क्षेत्र में पड़ता है। बरदार ने कहा कि बस यानी चित्तूर से तेलंगाना के भद्रचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में बस दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह अल्लुप्पूरी सीताराम राजू जिले में एक बस सड़क से नीचे गिरकर पलट गई।

पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे। इममें से छह लोग सुरक्षित हैं। पुलिस आधीशक (एसपी) अमित बरदार ने बताया कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चित्तूर-मोडुपिल्ली घाट सड़क पर

अमित शाह की भविष्यवाणी होने लगी सच!

कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व से माँगने लगे हिसाब



नई दिल्ली। हम आपको बता दें कि मोहम्मद मुक़िम के पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व न तो चुनावी धरातल समझ पा रहा है, न संगठन को मजबूत कर पा रहा है। यही कारण है कि हालिया उपचुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय झेलनी पड़ी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो दिन पहले ही लोकसभा में अपने भाषण में कांग्रेस

नेतृत्व पर तीखा वार करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी की लगातार हार का हिसाब एक दिन कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता ही आलाक़मान से माँगेंगे। 'देखा जाये तो अमित शाह की यह भविष्यवाणी राजनीति में सिर्फ एक बयान नहीं थी, आज की स्थिति देखकर लगता है कि वह सोधे कांग्रेस के भीतर फैलते असंतोष को बाँध चुके थे। हुआ

भी वैसा ही। ओडिशा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पत्र आ गया, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए और उसी दिन शशि थरूर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक से अनुपस्थित रहे, मानो पार्टी के भीतर उबलता लावा अब सतह पर फूटने लगा हो। हम आपको बता दें कि ओडिशा के पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुक़िम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सी साल पुरानी विरासत हाथ से फिसल रही है और इसका कारण है नेतृत्व में स्पष्टता की कमी, संगठनात्मक ढीलापन और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। मुक़िम ने मांग की है कि पार्टी की बागडोर ऐसे नेता के हाथ में दी जाए जो युवा, उन्मूर्तान और प्रभावी जनसंपर्क क्षमता रखता हो। उन्होंने इस संदर्भ में प्रिंक्क गांधी

राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा

संसद भवन की पहली मंजिल से, मैंने आतंकवादियों को भागते देखा था

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि जब 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हमला हुआ था तब वह लोकसभा के सदस्य थे और संसद भवन की पहली मंजिल से, उन्होंने आतंकवादियों को भागते देखा था। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने संसद पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कल, 13 दिसंबर, 2025 को संसद भवन पर हुए दुखद आतंकवादी हमले की चौबीसवीं बरसी है। यह हमला 13 दिसंबर, 2001 को हुआ था। उन्होंने कहा, उन दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, जब हमारे लोकतंत्र के प्रतीक अर्थात् भारतीय संसद की नींव को कमजोर करने के लिए उन आतंकियों ने निशाना बनाया,



सभापति ने कहा लोकसभा के सदस्य के तौर पर, मैं उस दुखद समय का साक्षी बना था। संसद भवन की पहली मंजिल से, मैंने आतंकवादियों को भागते देखा था। उन्होंने कहा कि इस हमले में देश के कई बहादुरों को खो दिया जो द्वितीय वीरता का प्रदर्शन

करते हुए हमलावरों और लोकतंत्र के इस मंदिर के बीच अडिग होकर खड़े रहे। आइए हम उन बहादुर आत्माओं को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और निस्वार्थ वीरता यहां मौजूद सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमारा पावन दायित्व है कि हम उन लोकतांत्रिक आदर्शों को आगे बढ़ाएं जिन्होंने हमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभापति ने कहा, इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनरुद्देशित करें और अपने मातृभूमि की एकता, अखंडता और संरक्षण की रक्षा के अपने संकल्प की पुनरुद्दिष्ट करते हैं।

ममता बनर्जी के बचाव में उतरे सपा सांसद वीरेंद्र सिंह,

उन्होंने बगावत के बारे में महिलाओं और

सरकार को आगाह किया

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी ने बगावत के बारे में महिलाओं और सरकार को आगाह किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा के दौरान महिलाओं से मतदाता सूची में नाम कटने पर लड़ई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था। इस पर शुक्रवार को सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, यदि अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है तो उसका अंतिम परिणाम बगावत होता है। उन्होंने इस बगावत के बारे में महिलाओं और सरकार को आगाह किया है समाचार एजेंसी से बातचीत में सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश और

मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, एसएसआईआर की समय सीमा उन्हें बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह जिस चालाकी के साथ समय कम देकर किया, उन्होंने बीएलओ के ऊपर इतना दबाव डाला कि कहीं ने आत्महत्या तक कर ली। वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कई बीएलओ ने अपने डाटा को कंश्लैट करने के लिए बिना विजिट के लाखों मतदाताओं को सी-कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में उन सी-कैटेगरी के मतदाताओं को कैसे ठीक किया जाएगा? यह बहुत बड़ा चालेंज है। उन्होंने कहा, हमने अपने सभी बीएलओ को काम में लगाया है।



श्रीनगर। देशभर में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए उम्मीद के डाटाबेस में पुरानी प्रविष्टियों की तुलना में कुल 3,55,312 वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से कम पाई गई हैं। यह जानकारी हाल ही में जारी आंकड़ों और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा उठाए गए सवालियों के बाद चर्चा में है। महबूबा मुफ्ती



संख्या 32,533 थी, जो 2025 में घटकर 25,293 रह गई यानी 7,240 प्रविष्टियां अचानक रिकॉर्ड से हट गईं। महबूबा मुफ्ती ने यही आंकड़े अपने आधिकारिक श्पेक्स हैडल के जरिए साझा करते हुए गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर पहले से ही सवाल हैं और इतनी बड़ी संख्या में संपत्तियों का रिकॉर्ड से गायब होना बेहद चिंताजनक है। हिंसा, ध्वस्तीकरण और मुस्लिम समुदाय को हाशिये पर धकेलने की घटनाओं के बीच वक्फ भूमि का क्षरण एक और बड़ा वार जैसा महसूस होता है। आखिर यह सब कहा जाकर रुकेगा? महबूबा मुफ्ती ने सरकार से इस पूरे मुद्दे पर स्पष्ट जवाब और विस्तृत जांच की मांग की है।

वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर छिड़ा विवाद,

महबूबा मुफ्ती ने गहन जांच की मांग की

सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने सदन में प्रश्न

उठाया कि क्या एसआईआर के माध्यम से वास्तव में मतदाता-सूची को शुद्ध करना मकसद है या लखित वोटों को हटा कर राजनीतिक फायदे हासिल करना लक्ष्य है। संजय सिंह ने संवैधानिक धारा 327 और लोकप्रतिनिधित्व कानून 1950 के हवाले से स्मरण कराया कि चुनाव आयोग के अधिकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर हैं और किसी भी बड़े पैमाने पर वोट कटौती की घटनाएं सामने आई हैं और ये कटौतियाँ लोकतंत्र की जड़ों को हिला रही हैं यह अगर इन कटौतियों का औचित्य नहीं बताया गया तो बहुमत-प्राप्ति के लिए सिंह ने दिल्ली के उदाहरण का जिक्र

करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की नयी दिल्ली विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले 42,000 मतदाता नाम अचानक काट दिए गए कृ यह आकड़ा हमारे पास है और हमने इस पर चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी भेजी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट कटौती की घटनाएं सामने आई हैं और ये कटौतियाँ लोकतंत्र की जड़ों को हिला रही हैं यह अगर इन कटौतियों का औचित्य नहीं बताया गया तो बहुमत-प्राप्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया में घपला सिद्ध होगा।

राहुल ने वायु प्रदूषण पर लोकसभा में चर्चा

की उठाई मांग, सरकार बोली- तैयार हैं हम

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों के वायु प्रदूषण की चपेट में आने का विषय शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को संसद में विस्तृत चर्चा कराने के साथ इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना सामने रखनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह विषय कार्य मंत्रणा समिति (बीएसपी) की बैठक में उठा था और सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने कहा, हमारे ज्यादातर बड़े शहरों पर जहरीली हवा की चादर पसरी हुई है, बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होती है... लोगों को कैन्सर जैसी बीमारियां हो रही हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सहमत होंगे। उनका कहना था कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए और उसमें आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधान को लेकर बात हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक योजना पेश करनी चाहिए।



महाप्रबंधक की उपस्थिति में नवनिर्मित फामेसीं वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ सफाई कर्मी परशुराम प्रसाद



गोरखपुर,: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु नित नये-नये कदम उठा रही है, इसी क्रम में रेल कर्मचारियों के बेहतर इलाज एवं सुविधापूर्ण तरीके से दवा उपलब्ध कराने हेतु ललित नरायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर में नवनिर्मित फामेसीं विंग एवं बाहिरंग प्रखण्ड के फसाड का उद्घाटन

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर की उपस्थिति में चिकित्सालय के वरिष्ठ सफाई कर्मी श्री परशुराम प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री अभय कुमार गुप्ता, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री संजय सिंहल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि, प्रधान

वित्त सलाहकार श्री अमरजीत गौतम, चिकित्सा निदेशक डा. मो. ए. ए. खान, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डा. नन्द किशोर, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डा. फहीम अहमद, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डा. अनिता शर्मा, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डा. तनु बर्मा सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी, डॉक्टर, चिकित्सकीय

सुपरवाइजर एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री बोरवणकर सहित प्रमुख विभागाध्यक्षों ने चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। महाप्रबंधक श्री बोरवणकर ने नव निर्मित फामेसीं वार्ड में उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक सुविधाओं का

दवा वितरण को सुचारू एवं सुविधाजनक बनायेंगे। फामेसीं वार्ड में मरीजों तथा उनके परिजनों को बैठने हेतु पर्याप्त एवं उत्तम व्यवस्था के साथ ही साथ पुरुष एवं महिला हेतु अलग-अलग प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा निदेशक डा. मो. ए. ए. खान ने नवनिर्मित फामेसीं वार्ड के बारे में महाप्रबंधक को अवगत कराया।

रेल सुरक्षा रिकॉर्ड सुधार में वृद्धि : वार्षिक दुर्घटनाएं 2004-14 के औसत 171 से घटकर 2025-26 में अब तक 11 रह गई हैं

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) नई रेल लाइन (6,753 करोड़ रूपए की लागत वाली) को मंजूरी मिली

गोरखपुर : भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) नई रेल लाइन परियोजना को लागत-साझाकरण के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा, 70 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि की पूरी लागत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 1617 करोड़ रुपये की भूमि लागत सहित परियोजना का विस्तृत अनुमान 6753 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था। हिमाचल प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के मुकाबले, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केवल 82 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध कराई गई है। परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर से बेरी तक की भूमि अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है। भूमि की अनुपलब्धता परियोजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। परियोजना पर अब तक कुल व्यय 5,252 करोड़ रुपये है। लागत-साझाकरण व्यवस्था के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार को 2,711 करोड़ रुपये देने थे। हालांकि, उन्होंने केवल 2,711 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं। उन्होंने लागत में अपना हिस्सा 847 करोड़ रुपये हिस्से के रूप में जमा कर दिया है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पास 1,863 करोड़ रुपये शेष हैं और इस कारण परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन न करने के कारण इस परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है। परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। केंद्र सरकार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर है, हालांकि सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए वर्ष 2009-14 में ₹. 108 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹. 2716 करोड़ बजट आवंटित किया गया जो वर्ष 2009-14 की तुलना में 25 गुना से ज्यादा अधिक है।

रेल प्रशासन की यात्रियों से अपील है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा प्रारम्भ करे

गोरखपुर,: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन अपने रेल यात्रियों को सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ रेल राजस्व की क्षति रोकने के लिए व्यापक कदम उठायें जा रहे है। इसी क्रम में महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर के निर्देश पर प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में वाणिज्य अधिकारियों की टीम ने 01 से 11 दिसम्बर, 2025 तक गोरखपुर से सीवान, गोरखपुर से बस्ती एवं गोंडा, गोरखपुर से सिसवा बाजार तथा गोरखपुर से सलेमपुर रेल खण्डों में विशेष टिकट जांच अभियान आयोजित किया, जिसमें अनधिकृत यात्रियों/बिना टिकट यात्रियों एवं पैन्ट्रीकार तथा ऑन बोर्ड स्टाफ के आई.डी. की जाँच की गयी, जिसके फलस्वरूप बिना टिकट/अनियमित टिकट के साथ/बिना बुक सामान के कुल 1434 मामले पकड़े गये, जिनसे कुल रूपया 9,24,414/- (नौ लाख चौबीस हजार चार सौ चौदह रुपए) के रेल राजस्व की वसूली की गयी। यात्रियों की सुविधा एवं रेल राजस्व की क्षति रोकने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मंडल पर निरन्तर स्पॉट चेक, एम्बुश चेक, किलाबंदी चेक आयोजित किये जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर स्टेशनों एवं गाड़ियों में आगे भी बिना टिकट यात्रा, बिना बुक किये गये सामानों की जांच, अनियमित यात्रा आदि विशेष टिकट जांच अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

कोहरे में सुरक्षित टेज्ज संचालन के लिए 980 फॉग सेफ डिवाइस की व्यवस्था

गोरखपुर,: सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा, रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसे सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए निरन्तर कार्य किया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में इस क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए संरक्षित टेज्ज संचालन हेतु सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल 980 फॉग सेफ डिवाइस की व्यवस्था की गई है, जिनमें से लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 250 तथा वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराये गये है। सभी प्रकार के सिगनल पोर्टों पर ल्यूमिन्स स्ट्रिप लगाई गई है, सिगनल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग करा दिया गया है। समपासों पर लगे बैरियर पर ल्यूमिन्स स्ट्रिप लगाई गई है। कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित एवं अपेक्षाकृत तेज टेज्ज संचालन में आधुनिक जी.पी.एस. आधारित फॉग सेफ डिवाइस का महत्पूर्ण योगदान है। इस डिवाइस के उपयोग में आने के पूर्व कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा अनुमेष थी। जबकी फॉग सेफ डिवाइस के लोको में लग जाने के बाद अधिकतम अनुमेष गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई अर्थात पहले की तुलना में अब टेज्जे कोहरे के दौरान 25 प्रतिशत ज्यादा गति से चल सकती हैं। इस फॉग सेफ डिवाइस के माध्यम से आने वाले सिगनल की जानकारी मिलने से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फॉग सिग्नल मैम भेज कर डेटेनेटर (पटाखा) लगाने की आवश्यकता भी खत्म हुई है। कोहरे के दौरान पूर्ण ब्लॉक पद्धति एवं स्वचालित ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों के संचालन के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों की काउंसलिंग की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में सभी रेल खण्डों पर सभी यात्रियों एवं मालगाड़ियों में फॉग सेफ डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटरियों के निगरानी के लिये रात्रिकालीन पेट्रोलिंग की जा रही है।

गोरखपुर,: रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे सेमीफाइनल मैच में पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रतिद्वंदी टीम सत्र में अपने शानदार प्रदर्शन से पश्चिम रेलवे को 47-39 अंको से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रातः काल के अन्य मैच में उत्तर रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को 41-29 अंकों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया तथा सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच हुआ, जिसमें उत्तर रेलवे ने 55-48 अंको से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की। इस अवसर रेलवे सुरक्षा बल के

के तत्त्वावधान में 10 से 13 दिसम्बर, 2025 तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में खेली जा रही 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता-2025 के तीसरे दिन 12 दिसम्बर, 2025 को सायं सत्र में खेले गये

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर के मुख्य अतिथ्य में प्रतियोगिता का फाइनल मैच 13 दिसम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे के बीच खेला जायेगा।

संक्षिप्त खबरें

बभनान क्षेत्र में 10 घंटे गुल रही बिजली

बभनान। बभनान- हरैया के बीच 33 केवी लाइन पर सुबह 6 बजे सूखा पेड़ गिर गया। जिससे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। बभनान उपकेंद्र से नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में पूरे दिन बिजली गुल रही। किसानों को खेत की सिंचाई करने के लिए दिन भर परेशान नजर आए। वहीं बिजली न रहने कारोबार भी प्रभावित रहा। छोटे- बड़े कारखाने विद्युत आपूर्ति ठप होने से संचालित नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से चोरखरी गांव के पास दो इंसुलेटर जल गए थे। यह फाल्ट खोजने में विद्युत निगम की टीम को काफी समय लग गए। दोपहर बाद फाल्ट का पता चला तो टीम मरम्मत कार्य में जुटी। विद्युत आपूर्ति बहाल करने में शाम चार बजे गए। जिससे दिन में लगभग 10 घंटे आपूर्ति बाधित रही। उपकेंद्र से जुड़े गौर फीडर, पैकोलिया फीडर, बेदीपुर फीडर व नगर पंचायत के टाउन फीडर पर आपूर्ति बाधित रही।

धंधेबाज हुए भूमिगत निशाने पर दवाओं की कई और फर्में

बस्ती। देश भर के दवा बाजार में कोडीन युक्त सिरप की आपूर्ति का मामला गर्म हुआ तो बस्ती भी चर्चा में आ गया। दवा व्यापार की आड़ में कोडीन युक्त सिरप के धंधे से जुड़े कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं। दवा कारोबार में अच्छी खासी रसूख वाले कुल आठ लोग पुलिस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। पुरानी बस्ती और कोतवाली थाने में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पूरब के इस मध्य अंचल में बस्ती समेत आसपास के जिले और नेपाल सीमा तक कोडीन युक्त सिरप सप्लाई के यह मुख्य किरदार बताए जा रहे हैं। अभी इनके नेटवर्क में और भी लोगों के शामिल होने की खबर मिल रही है। पुलिसिया जांच आगे बढ़ने पर कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। बस्ती में एक महीने के भीतर ताबड़तोड़ कोडीन युक्त सिरप की दो खेप पकड़ी गई। पहली बार नवंबर में पुरानी बस्ती क्षेत्र के खुशबू गोयल पत्नी शंकर गोयल के दवा गोदाम में 15,696 बोतल कोडीन युक्त सिरप की खेप पकड़ी गई थी। दूसरी बार तीन दिन पहले 9 दिसंबर को कोतवाली क्षेत्र के गणपति फार्मा के माध्यम से 1.72 लाख शीशी कोडीन युक्त सिरप के खपाने का मामला सामने आया। इसमें स्थानीय चार अन्य फर्मों की ओर से सप्लाई करने भूमिका पकड़ में आई। संबंधित फर्मों के संचालकों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। पुलिस रडार पर आ चुके दवा व्यवसाय से जुड़े यह चेहरे अब गिरफ्तारी की भय से भूमिगत बताए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ कोडीन युक्त सिरप बरामद होने के साथ बड़ी मात्रा में इसकी खेप खपाने वाले धंधेबाज पुलिस पकड़ से अभी दूर हैं। जबकि इनका नाम सामने आने के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों में हलचल बढ़ गई है। इन फर्मों के जरिये सप्लाई लेकर कोडीन युक्त सिरप बेचने वाले दवा दुकानदार की घड़कने भी बढ़ी हुई है। उन्हें आशंका है कि मुख्य किरदार पकड़े जाने के बाद उनके नाम का भी खुलासा हो सकता है।

कोड़री गांव में मिला व्यवसायी का शव, हत्या की आशंका

मानिक चंद। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बस्ती-बांसी मार्ग के कोड़री गांव के पास बुधवार की देर रात गल्ला व्यवसायी का शव सड़क किनारे मिली। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है।वाल्टरगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वालों के अनुसार, रूधौली थाना क्षेत्र के नटाई कला गांव निवासी नीरज सिंह (25) बुधवार की शाम करीब चार बजे किसी काम से नवीन कृषि उत्पादन समिति मंडी बस्ती गए थे। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो मां शांति देवी ने फोन किया। नीरज ने बताया कि हरैया में हैं, मां ने जल्दी घर आने की बात कहकर फोन काट दिया। नीरज के चाचा रणवीर सिंह ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे किसी का फोन आया कि नीरज का शव व पल्सर बाइक कोड़री गांव के पास पड़ा है। इसके बाद वह लोग मौके पर पहुंचे तो देखा पुलिस भी मौजूद है। नीरज के चाचा ने बताया कि मामला लेनदेन का और भतीजे की हत्या कर गई है। वाल्टरगंज के थानेदार जयवर्धन सिंह ने बताया कि परिवार वालों ने फिलहाल तहरीर नहीं दी है। परिवार वाले हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं, छानबीन की जा रही है।

दो जोड़ों में कराया समझौता

बस्ती। पारिवारिक मनमुटाव से अलग-अलग रह रहे दो जोड़ों को बृहस्पतिवार को पुलिस ने फिर एक साथ रहने के लिए राजी कर लिया। पिंग बूथ पर दोनों जोड़ों की काउंसिलिंग की गई। पुलिस के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र की रहने वालीपूरम पति मंगरू से नाराज होकर अलग रहती थीं। इसी तरह रजली निवासी बेबीनाज की भी पति सत्तार अहमद से रिश्ते ठीक नहीं थे। पिंग बूथ पर तैनात महिला सिपाहियों ने दोनों जोड़ों को एक साथ रहने के लिए राजी कराया।

राष्ट्रीय लोक अदालत कल, तैयारियां पूरी

बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें सुनाह-समझौते से मामले का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को प्रचार वाहन भी जिला जज शमसुल हक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को जनपद न्यायालय, कलकट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलों, बैंक वसूली के मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद, विद्युत व जलकर विवाद के निस्तारण किए जाएंगे।

अनियोजित तरीके से बना रहे थे नाला, टीम ने पकड़ीं खामियां

बस्ती। शहर में अनियोजित विकास के जरिये नगरीय विकास को आए बजट को जैसे-तैसे खपाने का खेल पकड़ा गया है। निर्माण संबंधी जांच में इसका खुलासा हुआ है। अब ऐसे निर्माण कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है। निर्माण में जो खामियां मिली हैं उसमें सुधार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बता दें कि शहर में 15वें वित्त समेत अन्य उपलब्ध बजट से नौ छोटे-बड़े नाले बनाए जा रहे हैं। दो करोड़ रुपये की इस परियोजना में पहले से खामियां मिल रही थीं। नागरिकों की ओर से की गई शिकायत के बाद ईओ अंगद गुप्ता एक्शन में आए। उन्होंने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई और जांच कर एक पखवारे में रिपोर्ट मांगी थी। क्रमवार नौ चिह्नित नाले की जांच हुई। सबसे पहले नालियों की स्थिति का निरीक्षण किया। इसमें कई जगहों पर स्लैब टूटी हुई पाई गई। इसके अलावा नाली के ढक्कन में प्रयुक्त सरिया की गुणवत्ता की भी जांच की गई। फीते से माप लेकर सरिया की मोटाई जांची गई और यह देखा गया कि तकनीकी मानकों के अनुसार सामग्री का प्रयोग हुआ है या नहीं। आड़ा-तिरछा नाले, ईट भी खराब आदि की रिपोर्ट है। कई हिस्सों में नाली पूर्ण नजर नहीं आई और मानक के तहत निर्माण नहीं होना पाया गया। जांच टीम ने इन खामियों को नोट करते हुए मौके पर साक्ष्य भी एकत्र किया।

संपादकीय

बच्चे बचपन

पश्चिमी देश, जिस सोशल मीडिया के गुणगान करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझ में आने लगी है। सुगबुगाहट तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक प्रतिबंधों को लेकर हो रही है, लेकिन इस दिशा में पहल करने का साहस आस्ट्रेलिया ने सुधारवादियों के दबाव में उठाया है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि बच्चों के बच्चे होने के अधिकार और माता-पिता की मानसिक शांति के अधिकार की रक्षा हो सके। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि यह सुधार जिंदगियां बदल देगा। साथ ही आस्ट्रेलिया के बच्चों को बचपन जीने का मौका देगा। आज दुनिया के तमाम देश मंथन कर रहे हैं यदि आस्ट्रेलिया यह पहल कर सकता है तो वे क्यों नहीं कर सकते। इनमें वे तमाम अभिभावक भी शामिल हैं जो अपने बच्चों की आत्महत्या के लिये सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में यदि सोशल मीडिया मंच 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें करीबन पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुमाना चुकाने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है। आस्ट्रेलियाई सरकार क्रिसमस तक मूल्यांकन करेगी कि ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित हुए हैं। निस्संदेह, आस्ट्रेलिया की पहल ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की मुहिम को नई ऊर्जा दे दी है। कमोवेश, भारत जैसे देश भी सोशल मीडिया की असामाजिकता का दंश झेल रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ ऑनलाइन बुलिंग से लेकर ऑनलाइन ठगी तक के तमाम मामले गाहे-बगाहे सामने आते रहते हैं। विडंबना है कि आज सोशल मीडिया पर प्रसारित वयरकों की सामग्री से बच्चे जाने-अनजाने में परिचित हो रहे हैं। वे समय से पहले वयरस्क हो रहे हैं। जिससे समाज में तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही हैं। निस्संदेह, इससे आने वाले समय में घातक सामाजिक विद्रूपताएं पैदा हो सकती हैं। दरअसल, बच्चों के लगातार घंटों कथित सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से उनमें तमाम शारीरिक व मानसिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं। उन्हें संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले निहित स्वार्थी तत्व दे रहे हैं। जो कि भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इतनी अश्लील व द्विअर्थी सामग्री का प्रवाह है कि हमारे किशोर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया के घातक प्रभाव के चलते आज बच्चों के नायक बदल गए हैं। उनके आदर्श बदल गए हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। सोशल मीडिया के कतिपय मंचों पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने किशोरों में ब्रह्मचर्य के भारतीय मूल्यों को ताक पर रख दिया है। विडंबना यह है कि घंटों सोशल मीडिया पर बैठे रहने वाले बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। जिससे उनमें मोटापा व अनेक गैर संक्रामक रोग पनप रहे हैं। वे किशोर अवस्था में मधुमेह आदि उन रोगों के शिकार बन रहे हैं जो कभी बड़ी उम्र के लोगों को हुआ करते थे। इस संकट का एक घातक पहलू यह भी है कि मोबाइल पर लगातार सोशल मीडिया के कार्यक्रम स्कॉल करने वाले बच्चों की मानसिक एकाग्रता बाधित हो रही है। जाहिर है इसका प्रभाव उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ेगा। एक समय दुनिया के तमाम देशों में जिन भारतीय प्रतिभाओं का डंका बजता था, शायद भविष्य में ऐसा न हो। घंटों सोशल मीडिया पर बिताने वाले छात्रों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपनी पढ़ाई के लिये पूरी तरह एकाग्र हो सकेंगे। निरंतर कल्पना लोक में विचरण करने वाले बच्चे जब जीवन की हकीकत से जुड़ेते हैं तो टूटने-बिखरने लगते हैं। गाहे-बगाहे आत्महत्या करने वाले किशोरों के डेटा का यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से हम सोशल मीडिया के घातक प्रभाव की हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। आस्ट्रेलियाई पहल से सबक लेकर भारत के नीति-निर्घताओं को भी इस दिशा में गंभीरता से पहल करनी चाहिए। इस दिशा में थोड़ी भी देरी की देश को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

संसद के लिए काला दिन

66

क्रांति से शांति तक नामक फोटो प्रदर्शनी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय, सानेपा, ललितपुर में आयोजित किया गया था, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड आये, और इसके प्रकारांतर पीएम इन वेंटिंग, केपी शर्मा ओली भी पधारे। उस अवसर पर प्रचंड का नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा से क्या संवाद हुआ, वह सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर, बुधवार सुबह प्रचंड ने घोषणा की, कि पहले संसद में विरवास मत करा लेते हैं, फिर मैं कुर्सी छोड़ूंगा। एक साल 180 दिनों से प्रचंड सत्ता में हैं। तीसरे टर्म प्रधानमंत्री पद पर बने रहना कितना कठिन होता है, उसे यों समझा जाये कि अब तक उन्हें चार बार विरवास मत हासिल करना पड़ा है। अखिरी बार 20 मई, 2024 को प्रचंड को विरवास मत हासिल करना पड़ा था, तब उपेन्द्र यादव के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बुधवार शाम एमाले ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी।

भारत के संसदीय इतिहास में एक और काला अध्याय उस समय जुड़ गया, जब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एक अपशब्द के साथ चुनाव आयोग को जोड़ा। हालांकि श्री शाह के बयान से उस शब्द को हटा दिया गया है। मीडिया भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मामला भाजपा की साख का है। लेकिन इस मामले को न हल्के में लिया जाना चाहिए, न इसे उपेक्षित करना चाहिए। क्योंकि यहाँ सवाल संसद की मर्यादा का है।भारत की संसद पर आतंकी हमला, सदन के भीतर नोटों की गड़्ढी लहराना, बसपा के अल्पसंख्यक सांसद दानिशा अली को भाजपा के सांसद रमेश बिघूड़ी का अपशब्द कहना और भाजपा के बाकी सांसदों का उस पर हँसना, नए संसद भवन में दो युवकों द्वारा रंगीन धुआं छोड़ना, ऐसे कुछ प्रकरण हैं, जो गौरवशाली संसदीय इतिहास में दुरुस्वप्न की तरह हैं। इन घटनाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनसे सबक लेते हुए आईदा इन्हें घटने से रोका जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसमें न केवल नाकाम रही, बल्कि इस बार तो संसद के अपमान के लिए खुद गृहमंत्री ही

जिम्मेदार हैं।अमित शाह ने गुजरात की राजनीति से आगे बढ़कर दिल्ली तक का सफर काफी जल्दी तय किया। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह का सियासी कद भी बढ़ा। 2014 में भाजपा का अध्यक्ष पद संभालने के बाद वे 2019 में देश के गृहमंत्री बने और अब इस पद पर सबसे लंबे वक्त बनने वाले व्यक्ति



बन चुके हैं। मोदी-शाह की जोड़ी ने भाजपा को सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया है। मोदी का चेहरा और शाह की रणनीति भाजपा की जीत का असली कारक बताई जाती है। अमित शाह को तो आधुनिक चाणक्य तक कहा जाता है। हम नहीं जानते कि इस तरह की तुलना मीडिया के प्रचार की वजह से हुई या चापलूसी से, लेकिन कम से कम चाणक्य से गलती की उम्मीद तो न चाटुकारों को होगी, न भाजपा के कार्यकर्ताओं को। इस उम्मीद पर

बुधवार को पानी फिर गया, जब विपक्ष को घेरने में अमित शाह ने लोकसभा के भीतर अपशब्द का प्रयोग किया।राहुल गांधी, गौरव गोगोई जैसे सांसदों ने इसका प्रतिवाद किया तो संभवतःश्री शाह को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने आसंदी से कहा कि मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो उसे हटा दीजिए। अच्छी बात है कि

शब्द सोच-समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन भाजपा तो संसद को भी चुनावी मंच की तरह ही उपयोग में लाती है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के लिए रेनकोट पहन कर नहाने जैसी निम्नस्तरीय टिप्पणी कर चुके हैं, राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना शूर्पणखा की हंसी से कर चुके हैं। सदन में खड़े होकर बेबुनियाद बातें करना या विपक्ष पर मिथ्या आरोप गढ़ना भी भाजपा की आम रणनीति बन चुकी है। भाजपा को लगता होगा कि इस रणनीति में मर्यादा और नैतिकता के लिए जगह बनाई जाए तो फिर उसका असर कम हो जाएगा। संभवतःरू इसलिए गंभीर विषयों पर भी हल्केपन के साथ चर्चा की जाती है, जिसमें अपशब्द शामिल हो सकते हैं, इसकी

अमित शाह की टिप्पणी के बाद कई सांसद चिंता जतला रहे हैं कि संसद में ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसी कल्पना नहीं की थी। यह चिंता वाजिब है और यहीं विपक्ष की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ जाती है कि अब वो भाजपा को संसद को अपने राजनैतिक हितों का जरिया बनाने से रोके। देश के मीडिया को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। भाजपा के एजेंडे के अनुरूप टीवी चैनलों पर जब से हिंदू-मुस्लिम बहसों को बढ़ावा दिया गया, स्टूडियो का

माहौल बिगड़ चुका है। अब केवल चीखने-चिल्लाने कर ये बहसें सीमित नहीं हैं, बल्कि खुलकर अपशब्दों का इस्तेमाल और हाथापाई तक होने लगी है। समाज पर ऐसी बहसें किस तरह बुरा असर करती हैं, पहले इसकी चिंता थी। अब यही चिंता संसद की कार्रवाई पर होने लगी है। इसलिए अमित शाह द्वारा अपशब्द के इस्तेमाल पर गहन-गंभीर विमर्श होने चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसका निराकरण कैसे हो सकता है।फर्ज कीजिए कि अगर विपक्ष के किसी सांसद की तरफ से ऐसा होता तो भाजपा इस मामले पर कितना बवाल खड़ा करती। राहुल गांधी ने एक बार अपनी बहन प्रियंका गांधी के गाल स्नेह से खींच दिए थे, तो ओम बिड़ला ने फौरन उन्हें टोकते हुए सदन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी थी। क्या ऐसी ही नसीहत अमित शाह को भी फौरन नहीं मिलनी चाहिए थी। संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच तोखी बहसें हों, एक-दूसरे की कर्मियों को भरपूर गिनावा जाए, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाएं, लेकिन इन सबके बीच संसद की गरिमा हरहाल मेंक़ायम रहे, यहजिम्मेदारी हेतु संसद की है।हर सदन यह ब्यथ वाद स्वेच्छि-उद्देश्य की सबसे बड़ी पंचावत मेंलाखों लोगों ने अपनी आवाज उठाने की उम्मीदों के साथ भेजा है। संसद की हरेक मिनट की कार्रवाई सुचारु चले इसके लिए जनता अपनी कमाई माननीयों पर खर्च करती है। उनकेलिए तमाम तरह की रियायतेंदेकर खुद कष्ट उठाती है।इसके बाद अगर वहां काम करने की जगह अगर अपशब्द सुनने मिलें तो यह लोक और लोकतंत्र दोनों के साथ धोखा है।

हमारे हितों की अनदेखी कर हमसे दोस्ती मुमकिन नहीं



ब्रह्मा चेलानी
अमेरिका की भारत-नीति दिन-ब-दिन अधिक विद्वेषपूर्ण होती जा रही है, लेकिन उसे यह मालूम होना चाहिए कि दीर्घकालिक अमेरिकी रणनीतिक हितों के लिए भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई और शक्ति नहीं है। क्योंकि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता-जिनमें परमाणु क्षमता भी शामिल है- के लिहाज से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो एशिया पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका के वर्चस्व को बेदखल करने की चीन की कोशिशों को चुनौती दे सकता है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल से ही वरिष्ठ अमेरिकी

क्योंकि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता- जिनमें परमाणु क्षमता भी शामिल है- के लिहाज से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो एशिया पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका के वर्चस्व को बेदखल करने की चीन की कोशिशों को चुनौती दे सकता है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल से ही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के साथ साझेदारी को निर्णायक माना है। यह नीति कभी सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित नहीं रही थी। पिछले एक दशक में तो अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंध तेजी से गहराए थे- विशेषकर सैन्य इंटर-ऑपरेबिलिटी, खुफिया सहयोग और तकनीकी लेनदेन के स्तर पर। वास्तव में, भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़त का एक हिस्सा तो ट्रम्प के पहले कार्यकाल में घटा था। चीन पर दबाव बढ़ाने और पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता घटाने के साथ ही ट्रम्प ने भारत के साथ सहयोग को बढ़ाया, जो उनकी इंडो-पैसिफिक रणनीति के केंद्र में था। इसका असर भी स्पष्ट है रू भारत आज किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक सैन्य अभ्यास करता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच अमेरिका ने भारत को सतर्क रहने के कई कारण भी दिए। अफगानिस्तान से उसका अव्यवस्थित पलायन- जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ लेकिन जिसकी बुनियाद ट्रम्प द्वारा किए समझौते से पड़ी थी- ने अमेरिकी नेतृत्व की समझदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसने अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हवाले कर दिया।

अधिकारियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के साथ साझेदारी को निर्णायक माना है। यह नीति कभी सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित नहीं रही थी। पिछले एक दशक में तो अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंध तेजी से गहराए थे- विशेषकर सैन्य इंटर-ऑपरेबिलिटी, खुफिया सहयोग और तकनीकी लेनदेन के स्तर पर। वास्तव में, भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़त का एक हिस्सा तो ट्रम्प के पहले कार्यकाल में घटा था। चीन पर दबाव बढ़ाने और पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता घटाने के साथ ही ट्रम्प ने भारत के साथ सहयोग

को बढ़ाया, जो उनकी इंडो-पैसिफिक रणनीति के केंद्र में था। इसका असर भी स्पष्ट है रू भारत आज किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक सैन्य अभ्यास करता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच अमेरिका ने भारत को सतर्क रहने के कई कारण भी दिए। अफगानिस्तान से उसका अव्यवस्थित पलायन- जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ लेकिन जिसकी बुनियाद ट्रम्प द्वारा किए समझौते से पड़ी थी- ने अमेरिकी नेतृत्व की समझदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसने

अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हवाले कर दिया। चिंताएं 2022 में तब और बढ़ीं, जब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को अखेरामफरनेकेल आउटदिलानेमेंमदद की और फिर उसके एफ-16 बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की भी मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने भी पाकिस्तान के प्रति इस झुकाव को और तेज ही किया है, जिसका एक उदाहरण उससे की गई क्रिस्टोफ़ेरी डील है। अमेरिका ने अक्सर भारत के हितों की अनदेखी की है। इसके बावजूद रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लागू कराने के मामले में वह भारत से पूरी निष्ठा की उम्मीद करता रहा। भारत इससे सहमत नहीं हुआ और उसने डिस्कॉन्टेंट दर्श पर

रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। भारत को सुदूर यूरोप में चल रहे किसी संघर्ष के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की बलि देने का कोई कारण नहीं दिखा, खासकर तब, जब रूस पर पश्चिमी दबाव का सबसे बड़ा लाभार्थी चीन था। भारत इस समीकरण को पहले भी देख चुका है। 2019 में जब ट्रम्पनेईरान परकड़ेप्रतिबंध लगाए तो भारत अपने सबसे सस्ते और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों में से एक से वंचित हो गया था। चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने ईरानी कच्चा तेल भारी छूट पर खरीदा और वहां अपनी सुरक्षा मौजूदगी बढ़ाई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी यही पैटर्न उभरा। पश्चिमी बाजारों से रूस को अलग कर देने



के बाद उस पर लगाए प्रतिबंधों ने उसे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया, जिससे चीन को रूस से आने वाले ऊर्जा-आपूर्ति मार्गों को मजबूत करने की क्षमता मिल गई। अब चीन जानता है कि ताइवान पर कर्खवाई करने पर भी रूसी ऊर्जा तक उसकी पहुंच नहीं घटेगी। इस बार भारत ने भी रूसी तेल पर उपलब्ध छूट का लाभ उठाया। अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो भारत की आर्थिक क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को सीधे नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि आज भारत अमेरिका के प्रति अविश्वास से भर गया है और उसे रूस से संबंध मजबूत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे हमें बराबरी का दर्जा देना होगा। अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो हमें क्षति पहुंचाती हैं।

खाने-पीने की चीजों के दामों पर सरकार का अंकुश जरूरी

ऐसे में कई विश्लेषकों का मानना है कि मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकंस का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन महंगाई घटाने में नाकाम रहा है। सच पूछो तो राजनेता महंगाई से डरते हैं। अमेरिका में अंडे की कीमतें- और भारत में प्याज के दाम- उनकी घड़कने बढ़ा देते हैं। बहुतां का मानना है कि 1998 में प्याज की ऊंची कीमतों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तो खासा बदनाम है। यहां कुछ ही महीनों- और कभी-कभी तो कुछ ही हफ्तों में- टमाटर या प्याज की कीमतें दस गुना तक बढ़ या घट जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में पिछले नवंबर में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा था और हाल में वह 13 रुपए किलो पर बिका। टमाटर पिछले अक्टूबर में 65 रुपए किलो था, अब 35 रुपए किलो है। हम अक्सर बड़ी हुई कीमतों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि हालिया रुझान दिखाता है कि कीमतों का पेंडुलम दोनों दिशाओं में बराबर झूलता है। किसी भी व्यवसाय में आउटपुट-कीमतों में ऐसी अस्थिरता कारोबारी को हैरान-परेशान कर सकती है। कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? दो सरल उपाय हैं रू वैश्विक स्रोतों से खरीद और फूड प्रोसेसिंग। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि औद्योगीकृत देशों में फल-सब्जियों की कीमतें साल भर काफी स्थिर रहती हैं। इसका कारण यह है कि वे घरेलू फसल पर निर्भर नहीं रहते। वे वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़े रहते हैं और जिस भी गोलार्ध में मौसम अनुकूल हो, वहां से आयात करते हैं।



नीरज कौशल
महंगाई के मुद्दे ने दुनिया में कई चुनावों के नतीजे तय किए हैं। अमेरिका में कोविड के बाद महंगाई को काबू में न रख पाने की कीमत जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स को क्वाइट हाउस खोकर चुकानी पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कीमतें घटाने का वादा किया था, लेकिन उलटे उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे महंगाई और बढ़ी। उनका कोर वोट इससे नाखुश है। ऐसे में कई विश्लेषकों का मानना है कि मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकंस का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन महंगाई घटाने में नाकाम रहा है। सच पूछो तो राजनेता महंगाई से डरते हैं। अमेरिका में अंडे की कीमतें- और भारत में प्याज के दाम- उनकी घड़कने बढ़ा देते हैं। बहुतां का मानना है कि 1998 में प्याज की ऊंची कीमतों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तो खासा

बदनाम है। यहां कुछ ही महीनों- और कभी-कभी तो कुछ ही हफ्तों में- टमाटर या प्याज की कीमतें दस गुना तक बढ़ या घट जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में पिछले नवंबर में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा था और हाल में वह 13 रुपए किलो पर बिका। टमाटर पिछले अक्टूबर में 65 रुपए किलो था, अब 35 रुपए किलो है। हम अक्सर बड़ी हुई कीमतों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि हालिया रुझान दिखाता है कि कीमतों का पेंडुलम दोनों दिशाओं में बराबर झूलता है। किसी भी व्यवसाय में आउटपुट-कीमतों में ऐसी अस्थिरता कारोबारी को हैरान-परेशान कर सकती है। कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? दो सरल उपाय हैं रू वैश्विक स्रोतों से खरीद और फूड प्रोसेसिंग। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि औद्योगीकृत देशों में फल-सब्जियों की कीमतें साल भर काफी स्थिर रहती हैं। इसका कारण यह है कि वे घरेलू फसल पर निर्भर नहीं रहते। वे वैश्विक



में वे चिली या मैक्सिको से टमाटरों का आयात कर लेते हैं। वास्तव में शायद ही ऐसा कोई मौसमी उत्पाद है, जो अमेरिकी ग्रांसरी स्टोर्स में ऑफ-सीजन में भी उपलब्ध न होता हो। जब कैलिफ़ोर्निया या फ्लोरिडा की आपूर्ति कमजोर पड़ती है तो मैक्सिको, कनाडा, चिली, ग्वाटेमाला या कोस्टा रीका उसकी भरपाई कर देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की सस्ती मजदूरी, कम परिवहन लागत और उनका विशाल कोल्ड-स्टोरेज नेटवर्क अमेरिकी सुपरमार्केट की शेल्फों पर साल भर स्थिर कीमतें बनाए रखते हैं। लेकिन भारत में उपभोक्ताओं की रक्षा के नाम पर आयात-निर्यात और किसानों की रक्षा

के नाम पर निर्यात-निर्यात ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों के व्यापार तथा भंडारण के लिए आवश्यक वेल्यू चेन विकसित ही नहीं हो पाई। नतीजा यह है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे होती रहती हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात करें। अधिकांश पश्चिमी देशों में प्याज और टमाटर का बड़ा हिस्सा प्रोसेसर कर लिया जाता है- सूखे प्याज-टमाटर, कैन में स्टोर किए हुए स्लाइस या फिर प्याज-टमाटर की प्यूरी के रूप में। 2016 के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन बताता है कि अमेरिका में 33 प्रतिशत टमाटर प्रोसेस होते हैं, चीन में 14 प्रतिशत, जबकि भारत में यह अनुपात सिर्फ 0.3 प्रतिशत ही है। एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि अमेरिका में फलों और सब्जियों का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा प्रोसेस होता हैय जबकि भारत में यह 5 प्रतिशत से भी कम है। इस साल भारत में प्याज और आलू की भरपूर पैदावार ने महंगाई को नकारात्मक दायरे में पहुंचा दिया है। दुनिया बड़ती कीमतों से चिंतित है, लेकिन भारतीय उपभोक्ता नहीं। बहरहाल, यह याद रखना जरूरी है कि ये हालात तेजी से उलट सकते हैं। कीमतें जब बहुत नीचे चली जाती हैं, तो किसान अगले साल वही फसल उगाने से कतराते हैं और इसी से कीमतों में उछाल की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। आपूर्ति और मांग के बीच यह विसंगति कीमतों में अस्थिरता को तंत्र की स्थायी विशेषता बना देती है। ऐसे में आयात कीमतों को स्थिर रखने में कारगर हो सकते हैं। भारत के लिए जरूरी है कि बाजार से नियंत्रण घटाए, विश्व-व्यापार बढ़ाए और भंडारण व प्रोसेसिंग पर गंभीरता से निवेश करे। भारत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव खासा बदनाम है। इससे बचने के लिए सरकार क्या कर सकती है? दो सरल उपाय हैं रू वैश्विक स्रोतों से खरीद और फूड प्रोसेसिंग। इससे ऑफ-सीजन में भी हमारे ग्रांसरी स्टोर्स भरे रहेंगे।

ढाका |महिला ने एक अगस्त को गुलशन थाने में केस दर्ज कराया, जिसमें उसने लगातार यौन हिंसा के आरोप लगाए। पुलिस द्वारा तैयार चार्जशीट में कई प्रकार के सबूत शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट जगत में हलचल मचाने वाले एक मामले में 25 वर्षीय क्रिकेटर तोफैल अहमद रहमान को एक यौन शोषण केस में आरोपित किया गया है। क्रिकबज को रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि क्रिकेटर ने एक महिला को शादी का भरोसा देकर झूसे में लिया और बाद में उसके साथ कई बार यौन दुराचार किया। सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती दायर चार्जशीट के मुताबिक, महिला से क्रिकेटर का संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शुरू हुआ। दोनों के बीच नियमित बातचीत होने लगी, जिससे धीरे-धीरे एक रोमांटिक रिश्ता विकसित हो गया।शुरूआत में महिला ने तोफैल के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था, लेकिन जब क्रिकेटर ने शादी करने की इच्छा जताई, तो उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी का वादा और होटल में कथित यौन शोषण महिला ने पुलिस को बताया कि तोफैल उसे ढाका के गुलशन स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने महिला को अपनी पत्नी के रूप में परिचित कराया। इसी दौरान उस पर कथित रूप से जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है।

राधिका आप्टे बोलीं- 'आजकल की शोर वाली फिल्मों से अलग है साली मोहब्बत; पार्टनर और बच्चे को लेकर कही ऐसी बात

टिस्का चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 'साली मोहब्बत' में राधिका आप्टे और दिव्येंदु शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएँगे। फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म साली मोहब्बत की निर्देशक टिस्का चोपड़ा के बारे में बात करते हुए राधिका आप्टे कहती हैं, एक अभिनेता का निर्देशक होना बड़े ही फायदे की बात है। उसे अभिनय से जुड़ी मुश्किलें पहले से पता होती हैं तो कई चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे बातचीत भी एक अलग स्तर पर हो जाती है। टिस्का इस मामले में बेहद संतुलित हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें क्या चाहिए और फिर हमें अपने तरीके से किरदार निभाने की आजादी दी। दिव्येंदु बारीकियों पर काम करने वाले अभिनेता हैं वहीं अभिनेता दिव्येंदु शर्मा के साथ काम करने के अनुभव साझा करते हुए राधिका ने कहा, सेट पर माहौल हमेशा हल्का रहता था और हम दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। वह एक अच्छे अभिनेता हैं...बारीकियों पर काम करने वाले और क्रिएटिव। उन्हें काम करते देखना दिलचस्प रहता था। कई बार हम दोनों एक-दूसरे का सीन देखकर हंस देते थे। कुल मिलाकर उनके साथ काम करने का अनुभव सहज रहा। ऐसा किरदार पहले नहीं निभाया वहीं जब बात हुई किरदार की तो राधिका बोलीं, 'इस किरदार और मेरे पहले निभाए गए किरदारों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि यह बहुत शांत और अंतमूर्खी है। वह ज्यादा बोलती नहीं है, अपने आप में रहती है। इस तरह का स्वभाव मैंने पहले किसी किरदार में नहीं निभाया था। मनीष मल्होत्रा के साथ अलग या अनुभव मनीष मल्होत्रा के निमाता बनने और फिल्म में उनकी भूमिका पर राधिका का कहना है, 'मैं यह जरूर कहूँगी कि मुझे मनीष एक ईसान के तौर पर अच्छे लगते हैं। वह लोगों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। सेट पर यह मजाक चलता रहता था कि मेरे कपड़े फैशनेबल नहीं हैं, तो वह कहते थे कि इन्हें कितनी बार धोया जाए ताकि ये पुराने लगें। लेकिन साधारण कपड़ों में भी हर चीज बहुत सोच-समझकर तय की गई थी। फिल्म की दृश्य शैली में उनका नजरिया साफ दिखता है। मैंने उन्हें पहले रंगीला जैसी फिल्मों के लिए कपड़े डिजाइन करते देखा है, तो ऐसे में यह अनुभव मेरे लिए अलग रहा। आज की फिल्मों से अलग है 'साली मोहब्बत' फिल्म की शैली और कहानी को लेकर राधिका का बयान, आजकल ज्यादातर तेज, शोर वाली फिल्में बन रही हैं। ऐसे समय में साली मोहब्बत उनसे अलग है। यह एक शांत फिल्म है, जो बहुत धीरे-धीरे अपनी कहानी खोलती है। यह पूरी तरह एक जांच पर आधारित फिल्म है, जो वक्त लेकर आगे बढ़ती है।' ये पल खोना नहीं चाहती अंत में मातृत्व और मौजूदा जिंदगी को लेकर बात करते हुए राधिका ने कहा, 'इस समय मैं सिर्फ बच्चे की देखभाल में ही व्यस्त हूं। इसमें ही काफी थकान हो जाती है। हालाँकि, इसमें जो सुकून है वो और कहीं नहीं। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और मैं उनके ये पल खोना नहीं चाहती। यह करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रही हूं। अभी मैं इसी में खुश हूं। इस दौर ने मेरी प्रार्थमिकताएं पूरी तरह बदल दी हैं और फिलहाल मेरा सारा ध्यान मेरे बच्चे पर है।

धुरंधर की छप्पर फाड़ कमाई, महज 7 दिनों में ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म



बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म धुरंधर को लेकर खूब चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज को करीब 8 दिन हो गए हैं और यह बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाती नजर आ रही है। हाल ही में धुरंधर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसने केवल सात दिनों में भारतीय बाजार में 207 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म धुरंधर ने पहले दिन भारतीय बाजार में 28 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये,तीसरे दिन 43 करोड़, चौथे दिन 23.25, पांचवे दिन 27 करोड़ और छठे दिन 27 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है। सैकनिल्क की अली रिपोर्ट के अनुसार फिल्म धुरंधर ने सातवें दिन 27 करोड़ का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म धुरंधर ने भारतीय बाजार में सात दिनों में 207 करोड़ रुपये दे अधिक की कमाई कर ली है। बता दें, फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसका असर फिल्म के कलेक्शन पर भी देखने को मिला है। धुरंधर की खास बात है कि इसमें रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना और के किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

ऐश्वर्या राय संग तलाक की अफवाहों पर अभिषेक ने पहली बार दी प्रतिक्रिया-ये खबरें पूरी तरह झूठी और बेकार हैं



बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता इस साल काफी उतार-चढ़ावों से गुजरा। सोशल मीडिया पर अफवाहें सामने आईं कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और दोनों जल्द ही तलाक लेने जा रहे हैं। हालांकि, इन सब अफवाहों पर अभिषेक और ऐश्वर्या ने चुपचा साधे रही। वहीं, अब हाल ही में पहली बार एक्टर

ने अपने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है और इन अफवाहों को बेसलेस और बकवास बताया। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ तलाक की अफवाहों को लेकर कहा-अगर आप कोई सेंसिटिविटी हैं, तो लोग हर बात पर अटकलें लगाना चाहेंगे और उन्होंने जो भी बकवास लिखी है, वो पूरी तरह से झूठी है, वो

फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, बेकार और गलत हैं, लेकिन अब मैं कितना कहूँ, वो शादी से पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने आगे कहा-शादी से पहले, वो हमारी शादी के समय को लेकर अटकलें लगा रहे थे। फिर शादी के बाद, वो हमारे तलाक को लेकर अटकलें लगा रहे थे ये सब बकवास है। वो मेरी सच्चाई जानती हैं। मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ। हम एक

खुशहाल और हेल्दी परिवार में वापस लौटेंगे, जो सबसे अहम है। बस यही मायने रखता है। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ तलाक की अफवाहों पर बेटी आराध्या बच्चन के रिएक्शन का भी खुलासा किया और बताया कि आराध्या को इन अफवाहों के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि उनके पास पर्सनल फोन नहीं है। एक्टर ने कहा-मुझे उम्मीद है कि उसे पता नहीं होगा। वो बहुत समझदार लड़की है। वो एक बेहतरीन बच्ची है और उसकी मां ने बहुत अच्छा काम किया है।मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का एहसास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसकी प्रावरिटी है। उसके पास फोन नहीं है और वो 14 साल की है।



थलाइवा के नाम से मशहूर सुपरस्टार रजनीकांत का आज बर्थडे है। 12 दिसंबर को एक्टर अपना 75वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर फैस से ले कर सेलेब्स की खूब शुभकामनाएं मिल रही हैं।

इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थलाइवा को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए रजनीकांत के सिनेमई सफर की तारीफ की।पोस्ट में पीएम

ने लिखा, स्थिर रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर बधाई। उनकी परफॉर्मेंस ने कई पीढ़ियों को लुभाया है और बहुत तारीफें बटोरी हैं। उनके काम में अलग-अलग रोल और जॉनर हैं, जो लगातार नए बेंचमार्क

सेट करते हैं। यह साल इसलिए खास रहा क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे कर लिए। उनकी लंबी और हेल्दी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ। रजनीकांत के बर्थडे पर पीएम मोदी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अन्य यूजर्स भी कमेंट कर एक्टर को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस हे ड कांस्टेबल थे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले रजनी का नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। एक्टर ने अपने फिल्म करियर में कई सुपरहिट साउथ और हिंदी फिल्मों में काम किया और फैस के बीच थलाइवा के नाम से फेमस हुए।

कुछ हद तक हंसाती है कपिल शर्मा की फिल्म, बस मत करना यह गलती



कपिल शर्मा एक बार फिर अपनी सुपरहिट कमेडी फ्रेंचाइजी 'किस किसको प्यार करूँ' को लेकर रें पर आ गए हैं। कहानी से लेकर अभिनय तक, क्या उम्मीद लगा सकते हैं इस

फिर्य से? पढ़ें रिव्यू...

सौचिए अगर एक ही आदमी मोहन, महमूद, माइकल और मंजीत चार किरदार निभाए, चार धर्मों में अलग-अलग बीवीयां रखे तो उसका दृश्य क्या होगा? बस इतनी

कहानी है फिर्य किस किसको प्यार करूं 2 की। यहाँ जानिए कैसी है यह फिल्म? फिर्य की शुरूआत होती है भोपाल शहर के रहने वाले मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) से जो सानिया (वरीना) से बेहद प्यार

करता है। सानिया से शादी करने के चक्कर में मोहन के सामने ऐसी-ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे रूही (आयशा खान), मीरा (त्रिधा चौधरी) और जेनी (पारुल गुप्ता) से भी शादी करनी पड़ जाती है। अब अंत में मोहन अपना असली प्यार कैसे पाता है? यह आपको फिर्य देखकर पता चलेगा। कैसा है अभिनय? कपिल शर्मा कमेडी तो कर सकते हैं पर एक्टिंग में सिर्फ कमेडी नहीं करनी होती यह उन्हें समझना होगा। हालाँकि, उनका काम पहले से बेहतर है पर रोमांटिक गानों और इमोशनल सीन में वो फीके लगते हैं। हाँ, कॉमिक टाइमिंग और पंच मारने में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने यह फिल्म अपने कर््यों पर संभाली है। चार हीरोइन वाली इस फिर्य में आयशा और त्रिधा का काम अच्छा है। पारुल कहीं-कहीं फीकी रहीं। वरीना के तो एक्सप्रेश पूरी फिर्य में गायब ही रहे। मनजोत ने इस

फिल्म को बखूबी संभाला है। अखिलेंद्र मिश्रा और विपिन शर्मा जैसे मझे हुए कलाकार भी इस फिर्य के संभालते हैं। सुशांत का रोल छोट है पर उनका काम ठीक है। असरानी के कुल चार सीन हैं और उन्हें देखकर अच्छा लगता है।पूरी फिर्य में जैमी लीवर की ओवरएक्टिंग और एक ही टोन इंसिटेड करती है। कैसा है म्यूजिक? हनी सिंह का एक गाना ठीक-ठाक है। फिर्य की ओपनिंग में ही एक रोमांटिक ट्रैक आपको बोर कर देता है।त्रिधा और कपिल के बीच शूट हुआ एक गाना जबरदस्ती फिल्माया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक सिचुएशन के हिसाब से ठीक है। क्या बेहतर? यह फिर्य चार धर्मों की बात करती है पर कहीं भी ऐसा डायलॉग या सीन नहीं है जो किसी धर्म को आहत करे। यह कमाल राइटर का है। फिर्य में कपिल शर्मा, मनजोत सिंह, विपिन शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा जैसे कलाकार आपको हंसाते हैं। कुछ पंच और कुछ सीन अच्छे बन पड़े हैं।

सलमान खान की मुन्नी अब बन गई हैं स्टाइलिश मैडम, हषाली मल्होत्रा के नए लुक ने जीता दिल



बजरंगी भाईजान की छोटी-सी, मासूम मुन्नी अब बड़ी हो चुकी हैं और अपनी खूबसूरत अदाओं से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। हषाली मल्होत्रा जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट अखंडा 2 से कमबैक कर रही हैं, और उससे पहले वे लगातार अपने फैस के लिए

नई तस्वीरें शेयर कर रही हैं। एक समय साड़ी और सूट में नजर आने वाली हषाली का इस बार बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिला। उन्होंने टॉप और पैट्स में ऐसा स्टाइल दिखाया कि लोग कमेंट्स में कहने लगे मुन्नी इतनी बड़ी हो गई! पैट-टॉप में दिखीं बाँसी वाइब्स

17 साल की हषाली का फैशन सेंस कमाल का है। इस बार वे पेस्टल पिंक टॉप और व्हाइट हाई-वेस्ट पैट्स में दिखाई दीं। टॉप में शर्ट जैसा कॉलर और सिल्वर बटन थे, जो पूरे लुक को क्लासी बना रहे थे। वहीं, वाइड-लेग पैट्स और ब्लैक बेल्ट ने आउटफिट को फॉर्मल और स्टाइलिश टच दिया। जेब में हाथ डालकर दिया गया उनका एटीट्यूड-पोज लोगों को खूब पसंद आया। हषाली ने मिनिमल ज्वेलरी चुनी छोटे गोल्ड इयररिंग्स, दो ब्रेसलेट और चमकदार रिंग्स। फुटवियर भी आउटफिट से मैच होता दिखा। उन्होंने व्हाइट और पेस्टल पिंक वेजेज पहनी थीं, जिनकी छोटी हील्स आराम और स्टाइल दोनों बनाए रखती हैं। फैस बोले दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हषाली की तस्वीरें देखते ही लोग कमेंट्स करने लगे। किसी ने कहा, मुन्नी अब मैडम साहिबा बन गईं! तो किसी ने लिखा, आपको किसी की नजर न लगे मेरी सोनी कुड़ी। कई फैस तो उन्हें सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस बता रहे हैं।

78000 हुए बेघर, छतों पर फंसे लोग कई शहर कराए गए खाली

वाॅशिंगट। वाॅशिंगटन राज्य में लगातार बारिश ने ऐतिहासिक बाढ़ ला दी है। स्कैजिट और स्नोहोमिश नदियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए और कई शहर खाली कराए गए। पुल, सड़कें और घर बह गए, जबकि कई परिवार छतों पर फंसे मिले और हेलीकॉप्टर से बचाए गए। अमेरिका के वाॅशिंगटन राज्य में लगातार कई दिनों तक हुई तेज बारिश ने हालात बेहद भयावह बना दिए हैं। नदियां रिकॉर्ड स्तर तक भर गई हैं, पुल बह गए हैं और कई घर अपनी नींव से उखड़कर बह गए हैं। हजारों लोग छतों पर फंसे मिले और कई शहर पूरी तरह खाली कराए गए हैं। प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक बाढ़ करार दिया है। वाॅशिंगटन में आपातकाल लागू कर दिया गया है और करीब 78,000

लोगों को स्कैजिट नदी के आसपास के इलाकों से तुरंत निकाला गया। राज्यपाल बॉब फर्ग्यूसन ने



निवासियों से कहा कि यह सामान्य बाढ़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो राज्य ने पहले कभी नहीं देखी। कई नदियां अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं, जबकि मौसम विशेषज्ञों ने शुक्रवार तक और ज्यादा बाढ़ का खतरा जताया है। उफान पर नदियां

स्नोहोमिश नदी अपने पुराने रिकॉर्ड से करीब एक फुट ऊपर चली गई, जबकि स्कैजिट नदी भी माउंट वर्नन

में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई। कंक्रीट टाउन में नदी का पानी घरों के दरवाजे तक जा पहुंचा, कुछ घरों से मलबा लगातार बहता रहा। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पानी इतना ऊंचा उठ सकता है। 2003 की बाढ़

के बाद अब यह इलाका फिर बड़े संकट में है। बड़े पैमाने पर नुकसान पूरे राज्य में पुलों और हाईवे पर पानी भर गया है। कई सड़कें पूरी तरह बह गई हैं। स्टेट रूट 410 और इंटरस्टेट-90 के हिस्से बंद कर दिए गए हैं, जहां वाहन पेड़ों, कीचड़ और पानी में फंसे पाए गए। सीमावर्ती शहर सूमास, नुकसैन और एक्सन में हालत सबसे खराब हैं। सूमास का मेयर ब्रूस बोश ने कहा कि शहर लगभग तबाह हो गया है। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पार करने का रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ ही सिएटल-वैंकूवर अम्ट्रेक ट्रेन रोक दी गई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को छतों से निकाला गया कई परिवार अपने घरों की छतों पर फंसे मिले, जिन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला गया। सूमास के कुछ इलाकों में पानी 15

फीट तक भर गया और फायर स्टेशन भी तीन फीट पानी में डूब गया। वेलकम शहर में नदी कटान से दो मकान सीधे नुकसैन नदी में गिर गए। पूर्व सिएटल के स्नोकलमी में हिरणों का झुंड फुटबॉल मैदान में गर्दन तक पानी में तैरता दिखा। कई घरों में लोग पानी निकालने के लिए पंप चलाते नजर आए। अगले खतरे की चेतावनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे तीव्र तूफान और बाढ़ की घटनाएं जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का संकेत हैं। हालांकि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना वैज्ञानिक दृष्टि से कठिन है, लेकिन भारी बारिश और चरम मौसम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रविवार से एक और नया तूफानी सिस्टम राज्य में प्रवेश करेगा, जो और भारी बारिश लाएगा।

पाकिस्तान को 12 हिस्सों में तोड़ने की तैयारी

इस्लामाबाद। थिंक-टैंकों ने चेताया-इस कदम से अस्थिरता बढ़ेगी, इससे न केवल विद्रोह और फैलेगा बल्कि पाकिस्तान का क्षेत्रीय

नागरिक समूह इसे उनकी आजादी की मांग को दबाने और पहचान मिटाने की कोशिश बता रहे हैं। थिंक टैंकों ने पाकिस्तानी सरकार को



विघटन निकट भविष्य में लगभग तय हो जाएगा। पाकिस्तान में सेना और सरकार द्वारा चार प्रांतों को 12 प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठित करने की योजना ने आंतरिक असंतोष भड़का दिया है। आजादी और स्वायत्तता की मांगों को विखेरने की रणनीति बताई जा रही इस कवायद पर जहां इस्लामाबाद तेज प्रशासनिक सुधार का तर्क दे रहा है, वहीं सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राजनीतिक दल व

चेताया अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों कार्नेगी, वेस्ट एशिया एंड पाकिस्तान स्टडीज और इंटरनेशनल ब्राइसिस ग्रुप का आकलन है कि इससे न केवल विद्रोह और फैलेगा बल्कि पाकिस्तान का टूटना निकट भविष्य में लगभग तय हो जाएगा। सेना व सरकार पर आरोप है कि वे बलूचिस्तान, सिंध व केपी में उठ रहे आंदोलनों को कमजोर करने के लिए देश के मौजूदा चार प्रांतों को 12 नए प्रांतों में बांटने की रणनीति पर काम

कर रहे हैं। हालांकि चार प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने के अनौपचारिक खाके के तहत पंजाब को उत्तर, मध्य व दक्षिण पंजाब में सिंध को कराची-सिंध, मध्य-सिंध व ऊपरी-सिंध में रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को भी उत्तर, दक्षिण व आदिवासी खैबर प्रांत में बांटा जाना है। इसी तरह बलूचिस्तान को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में बांटा जाना है। सिंध, बलूचिस्तान, के पी में विरोध पाकिस्तानी सूचना-प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तगर से नए प्रांतों की रूपरेखा पर संकेत मिलते ही देश में सियासी प्रतिक्रिया विस्फोट हो गई। सिंध-पीपीपी के नेता बिलावल जरदारी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत सिंध को बांट नहीं सकती। यह सांस्कृतिक हमला है। सत्तारूढ़ पार्टी में सहभागी पार्टी ने इसे खतरनाक खेल बताया। बलूचिस्तान ने इसे बलोक पहचान मिटाने वाली चाल बताया। क्वेटा और तुर्बत में विरोध तेज हो गया है, जबकि केपी में इसे पख्तून भूगोल को खंडित करने का प्रयास बताकर विरोध किया जा रहा है।

फैज हमीद को मिली सजा तो बस शुरूआत! पाकिस्तानी सांसद का चौंकाने वाला दावा

इस्लामाबाद। आईएसपीआर ने खुलासा किया था कि फैज हमीद पर 9 मई, 2023 के दंगों में कथित सलिपता के लिए जांच चल रही थी, जिसके दौरान सैन्य भवनों और स्मारकों में तोड़फोड़ की गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (क्वक) के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को सेना के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में एक सैन्य अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद को दी गई सजा महज 'शुरूआत' हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह दो साल पहले सेना विरोधी दंगों में शामिल राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नए मामलों की बाढ़ आने का इशारा माना जा सकता है। फैज हमीद को गुरुवार को एक सैन्य अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई, जिसने उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और राजनीतिक

गतिविधियों में शामिल होने सहित कई आरोपों में दोषी पाया। हमीद के खिलाफ अभी कार्रवाई बाकी है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के बयान में कहा गया है,



'राजनीतिक तत्वों के साथ मिलीभगत करके निहित स्वाधों से प्रेरित राजनीतिक आंदोलन और अस्थिरता फैलाने में दोषी की सलिपता और कुछ अन्य मामलों से अलग से निपटा जा रहा है।' रिपोर्ट के अनुसार इस भाषा से फैज हमीद और कुछ अज्ञात राजनेताओं को अर्शात फैलाने के व्यापक प्रयास से जोड़ने का इशारा मिलता

है। इसके अनुसार यह संदर्भ पिछले साल से जारी सैन्य बयानों की श्रृंखला में नवीनतम है, जो शक का संकेत देता है और सरकार विरोधी राजनीतिक तत्वों के साथ

फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने संस्थान से गंदगी हटाने के लिए धन्यवाद दिया। इमरान खान के करीबी थे फैज हमीद इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सत्ता में रहने के दौरान हमीद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के करीबी लोगों में जल्दी ही अपनी जगह बना ली थी। कुछ खबरों के अनुसार, वह इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों के काफी करीब हो गए थे। नवाज शरीफ ने दी थी खुली धमकी 2020 में, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से हमीद और उनके पूर्व बॉस, जनरल कमर बाजवा पर तीन बार के प्रधानमंत्री को पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। सबसे सीधा आरोप गुजरांवाला में एक रैली के दौरान लगाया गया था, जहां नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल फैज, यह सब आपके हाथों से हुआ है और आपको इसका जवाब देना होगा।

टीपीपी के आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर किया हमला

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार रात को टीटीपी के आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से



कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना ऐसे समय में हुआ, जब गुरुवार को इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार रात को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों और पुलिस के बीच तीन घंटे तक गोलीबारी जारी रही। आतंकवादियों ने बनू जिले के हावैद पुलिस क्षेत्राधिकार में स्थित

शेख लैंड पुलिस चौकी को निशाना बनाया। पुलिस के बयान के अनुसार कई आतंकवादी मारे गए और कई घायल हुए। प्रवक्ता द्वारा जारी एक

बयान में कहा गया है कि फितना अल ख्वारिज के आतंकवादियों ने गुरुवार देर रात चौकी पर हमला किया। फितना अल ख्वारिज वह शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है। बयान में कहा गया है कि पुलिसकर्मीयों ने साहस और बहादुरी का परिचय दिया और समय रहते कार्रवाई करते हुए हमले को विफल करने में सफलता प्राप्त की। डीएसपी घायल पुलिसकर्मीयों से मिले गोलीबारी के दौरान पांच पुलिसकर्मीयों को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बयान में कहा गया है कि बन्नु के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सज्जाद खान के निर्देश पर अतिरिक्त कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके

को घेर लिया। इसमें कहा गया है कि बन्नु के डीआईजी और जिला पुलिस कार्यालय (टीपीओ) यासिर अफरीदी ने पुलिस के प्रयासों और क्षेत्र के लोगों के साहस और बहादुरी की सराहना की। इसके साथ ही डीएसपी ने बाद में अस्पताल में घायल पुलिसकर्मीयों से मुलाकात की। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब गुरुवार को इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि एक फुटबॉल मैच के दौरान आतंकवादियों द्वारा एक खेल के मैदान पर किए गए क्वाडकॉप्टर हमले में नाबालिगों सहित कम से कम सात लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। नवंबर 2022 में टीटीपी द्वारा सरकार के साथ युद्धविराम समाय करने और सुरक्षा बलों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों पर हमला करने की शपथ लेने के बाद घटनाओं में यह उछाल आया है। अक्टूबर में, इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा था कि आतंकवादी हमलों में वृद्धि और आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने के कारण देश में तीन महीनों में हिंसा में तेजी आई है।

क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कसेगा शिकंजा

इस्लामाबाद। क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने वाला है? ऐसा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों खासकर एक्स पर सरकार का सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इतना ही पाकिस्तान सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्मों को बड़ी चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री बरिस्टर अकील मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बड़ी चेतावनी दी है।



उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें बैन किया जा सकता है। बरिस्टर मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसका पाकिस्तान में लगभग 45 लाख उपयोगकर्ता हैं, सरकार के साथ सबसे कम सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक्स को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान में कार्यालय खोलने के लिए भी कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा सहयोग' मंत्री ने आगे कहा कि पैलेस्टाइन से जुड़े पोस्ट 24 घंटे में हटा दिए जाते हैं, लेकिन यहां हम आतंकवाद से जुड़े मामले की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म सहयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी ब्राजील जैसी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि ब्राजील में एक्स पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 5.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया और 22 मिलियन उपयोगकर्ताओं वाला प्लेटफॉर्म वहां अस्थायी रूप से बंद किया गया। इमरान खान के एक्स अटॉरंट की जांच बरिस्टर मलिक ने यह भी कहा कि इमरान खान के एक्स अकाउंट के मामले में जांच चल रही है। पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) ने इमरान से जेल में उनके 'एंटी-स्टेट' पोस्ट और विदेश नीति पर टिप्पणियों के बारे में सवाल किए हैं। इससे पहले, सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि जेल में रहने के दौरान उनके एक्स अकाउंट का संचालन कौन कर रहा है, इसकी जांच राष्ट्रीय साइबर ब्राइड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (पीटीए) को करने का आदेश दिया जाए।

थाईलैंड के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने की मंजूरी

बैंकॉक। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल को शुक्रवार को पार्लियामेंट भंग करने की शाही मंजूरी मिल गई, जिससे अगले साल की शुरूआत में आम चुनाव होंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल को शुक्रवार (12 दिसंबर) को संसद भंग करने के लिए शाही स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही देश में अगले साल की शुरूआत में आम चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। शाही आदेश जारी होने के 45 से 60 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा के चुनाव

कराए जाएंगे। इस दौरान अनुतिन चर्नवीराकुल सीमित अधिकारों के साथ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और नई बजट मंजूरी नहीं कर सकेंगे। सीमा विवाद के बीच राजनीतिक कदम इससे पहले प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल ने गुरुवार देर रात फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैं सत्ता वापस जनता को सौंपना चाहता हूं। पीएम का यह फैसला ऐसे समय आया है जब थाईलैंड कम्बोडिया के साथ वर्षों पुराने सीमा विवाद को लेकर बड़े पैमाने पर संघर्ष में उलझा हुआ है। इस हफ्ते की झड़पों में करीब

दो दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों ओर से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 13 महीने पहले ही बने थे प्रधानमंत्री बता दें कि अनुतिन चर्नवीराकुल सिर्फ तीन महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने पैटोंगटार्न शिनावत्रा की जगह ली है, जिन्होंने सिर्फ एक साल तक पद संभाला था। अनुतिन ने सितंबर में संसद में हुए मतदान में जीत हासिल की थी, जिसमें मुख्य विपक्षी पीपल्स पार्टी ने उनका समर्थन इस पद पर किया था। कि वे चार महीने के भीतर संसद भंग करेंगे और एक नई संविधान सभा के

लिए जनमत संग्रह कराएंगे। संविधान संशोधन विवाद बना कारण संविधान बदलने का मुद्दा इस समय के दं में है। अनुतिन की पार्टी भूमजथाई ने संविधान संशोधन के लिए जरूरी व्यवस्था में सीनेट के एक-तिहाई मतों को बरकरार रखने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी। यह विवाद संसद भंग होने की मुख्य वजह माना जा रहा है। पैटोंगटार्न सरकार से अलगाव अनुतिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री

पैटोंगटार्न शिनावत्रा की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन कंबोडिया के साथ सीमा तनाव से जुड़े एक राजनीतिक घोटाले के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी को गठबंधन से बाहर कर लिया। पैटोंगटार्न, जो पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावत्रा की बेटी हैं, उनको जुलाई में पड़ोसी देश कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन के साथ एक विवादित फोन कॉल के कारण नैतिक आधार उल्लंघन में दोषी पाए जाने के बाद पद से हटा दिया गया था। अनुतिन ने पैटोंगटार्न

की कैबिनेट में काम किया था, लेकिन कंबोडिया के साथ बॉर्डर पर तनाव से जुड़े एक राजनीतिक विवाद के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी को उनकी गठबंधन सरकार से वापस ले लिया। नई सरकार अल्पमत में फंस सकती है पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वह विपक्ष में ही रहेगी, जिससे नई सरकार अल्पमत में फंस सकती है। यह पार्टी लंबे समय से सेना समर्थित पुराने संविधान में बदलाव की मांग करती रही है, ताकि उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके।

कंजरवेटिव सांसद माइकल मा ने छोड़ी पार्टी पीएम कार्नी की पार्टी में हुए शामिल

टोरंटो। कनाडा में सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ जब मार्कहमड्यूनिनगविल के कंजरवेटिव सांसद माइकल मा अपनी पार्टी छोड़ पीएम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी में शामिल हो गए। मा ने कहा कि वे विभाजन नहीं, समाधान की राजनीति चाहते हैं और कार्नी का नेतृत्व देश की जरूरतों के लिए अधिक स्थिर व व्यावहारिक है। कनाडा की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां कंजरवेटिव पार्टी के सांसद माइकल मा ने अपनी पार्टी छोड़कर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल सरकार का दामन थाम लिया। माइकल मा ऑटारियो प्रांत की मार्कहम-यूनिनगविल सीट से सांसद हैं। वे पिछले एक महीने में दूसरे कंजरवेटिव सांसद हैं जिन्होंने लिबरल पार्टी ज्वॉइन की है। बात अगर माइकल मा के पार्टी छोड़ने के पीछे की कारण की करें तो अपने बयान में मा ने कहा कि वे राजनीति में

'समाधान ढूंढने, न कि विभाजन बढ़ाने के लिए आए थे। मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वह स्थिर और व्यावहारिक नेतृत्व दे रहे हैं जिसकी देश को जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे अपने इलाके के लोगों से रोजाना जिन समस्याओं के बारे में सुनते हैं, उन पर काम करने में कार्नी की सरकार बेहतर है। लिबरल पार्टी बहुमत के एक कदम करीब बता दें कि मा के शामिल होते ही लिबरल पार्टी संसद में बहुमत से सिर्फ एक सीट कम रह गई है। ऐसे में अगर वे बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें अपने बिल पास कराने के लिए किसी विपक्षी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजरवेटिव खेमे में नाराजगी दूसरी ओर माइकल मा के इस कदम से कंजरवेटिव पार्टी के खेमे में नाराजगी का माहौल है।

समाधान ढूंढने, न कि विभाजन बढ़ाने के लिए आए थे। मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वह स्थिर और व्यावहारिक नेतृत्व दे रहे हैं जिसकी देश को जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे अपने इलाके के लोगों से रोजाना जिन समस्याओं के बारे में सुनते हैं, उन पर काम करने में कार्नी की सरकार बेहतर है। लिबरल पार्टी बहुमत के एक कदम करीब बता दें कि मा के शामिल होते ही लिबरल पार्टी संसद में बहुमत से सिर्फ एक सीट कम रह गई है। ऐसे में अगर वे बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें अपने बिल पास कराने के लिए किसी विपक्षी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजरवेटिव खेमे में नाराजगी दूसरी ओर माइकल मा के इस कदम से कंजरवेटिव पार्टी के खेमे में नाराजगी का माहौल है।